

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी,  
अधिवक्ता,  
ई-179, स्ट्रीट नं०-९,  
खजूरी कॉलोनी, दिल्ली-110094.

न्याय अनुभाग-१

देहरादून : दिनांक १७ जून, 2016

विषय : मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पैनल अधिवक्ता के रूप में आवद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको पैनल अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रेतर 01 वर्ष की अवधि के लिए आवद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— उक्त आवद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3— आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-123/XXXVI(1)/2013-43 एक(1) /2003 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमत्य होगी।

4— साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति एवं एडवोकेट के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा आवासीस पता दूरभाष संख्या सहित उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)

सचिव

संख्या- ८१५८/यXXXVI(1)/2016-75/2007 T.C. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महासचिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकंदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. महानिवन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महाधिवक्ता कार्यालय, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. ईरला, चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(महेश वन्द्र कौशिया)

आमर सचिव